एच. एस. बी

एम . एम . पुंछी के समक्ष , जे .

सुरिंदर कौर , –अपीलार्थी

बनाम

मदन गोपाल सिंह–उत्तरदाता।

1979 का **एफ. ए. ओ. सं. 188–एम.**

12 मई, 1980।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)—धारा 27—सिद्धांत उसमें अंतर्निहित – ' संबंधित' शब्द धारा 27–क्षेत्र में आता है –कहा गया

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 27 को पढ़ने से पता चलता है कि विश्लेषणात्मक रूप से खंड निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है (1) न्यायालय के समक्ष 1 अधिनियम के तहत एक वैवाहिक कार्यवाही लंबित होनी चाहिए और कार्यवाही के निर्णय से पहले संपत्ति के निपटान के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए; (ii) संपत्ति के निपटान के संबंध में डिक्री में प्रावधान करना न्यायालय का दायित्व नहीं है और यह उसके न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है; (iii) इस प्रकार बनाया गया प्रावधान, यदि कोई हो, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए जैसा कि न्यायालय पार्टियों के बीच इक्विटी के समायोजन और आसपास की सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानता है! (iv) आदेश केवल उस संपत्ति को घेर लेगा जो विवाह के समय या उसके आसपास प्रस्तुत की गई थी, जिसका अर्थ है न केवल विवाह में, बल्कि विवाह से पहले या बाद में भी प्रस्तुत की गई थी।वह विवाह के समय के निकट होना चाहिए और उस समय की विस्तारित सीमा से बाहर की गई संपत्ति के लिए नहीं होना चाहिए; (v) इस प्रकार प्रस्तुत की गई संपत्ति या तो पत्नी या पति या दोनों के लिए हो सकती है; और (vi) जब अदालत को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, तो संपत्ति संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की हो सकती है।'संबंधित' शब्द अनिवार्य रूप से स्वामित्व के अर्थ में संपत्ति के स्वामित्व को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह केवल संपत्ति के साथ संबंध को दर्शाता है और एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से जोड़ने वाला शब्द है।एक सांसारिक उदाहरण देने के लिए, पति या किसी के द्वारा प्रस्तुत साड़ी में पत्नी को साड़ी की उपाधि का हस्तांतरण शामिल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से उसकी होगी और पति और पत्नी दोनों के लिए संयुक्त रूप से नहीं होगी, जैसा कि परिधान की प्रकृति से पता चलता है।इसी तरह, उसी तरीके से पति को प्रस्तुत किया गया सूट विशेष रूप से पति का होगा।किसी भी स्रोत से और उनमें से किसी एक को प्रस्तुत की गई संपत्ति और वस्तुएं जो वर्तमान की प्रकृति से, या दाता के इरादे से, या पति/पत्नी के मौन समझौते से,पति और पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त

रूप से उपयोग में, दोनों को संयुक्त रूप से संबंधित कहा जा सकता है। इस तरह की घटना का एक सांसारिक उदाहरण वैवाहिक घर में संयुक्त उपयोगकर्ता के लिए भोजन की मेज और कुर्सियों का एक सेट हो सकता है, चाहे कोई भी तथ्य हो।किस पति या पत्नी को उस निर्धारित समय के भीतर इसे उपहार के रूप में प्राप्त हुआ।उक्त भोजन की मेज और कुर्सियां स्पष्ट रूप से पति और पत्नी दोनों की संयुक्त होंगी और अधिनियम की खंड 27 के तहत आदेशों के अधीन होने में सक्षम होंगी।

(पैरा 4 और 5)

श्री आर . एस . शर्मा .पी . सी .एस ., वरिष्ठ उप –न्यायाधीश , चंडीगढ़ , दिनांक 10 अक्टूबर , 1979 के न्यायालय के आदेश से *पहली अपील, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने* का *आदेश दिया गया है।दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।*

सिविल विविध। 1663–सी –।।। 80।

श्रीमती सुरिंदर कौर द्वारा दायर आपत्ति याचिका। सिविल प्रक्रिया संहिता *के* आदेश *41 नियम 26 के तहत।*

उजागर सिंह। अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर *से /*

जी. आर. मजीठिया, अधिवक्ता, *प्रतिवादी की ओर से।*

जजमेन्ट

मदन मोहन पुंछी , जे .

(1), इस पहली अपील में एक टूटी हुई शादी को बचाने की समस्याएं शामिल हैं।वैवाहिक न्यायालय किस हद तक बचाव अभियान और इसकी गतिविधि का क्षेत्र युद्धरत तलाकशुदा पति/पत्नी के बीच लड़ाई का बिंदु है जिसमें संपत्ति का निपटान शामिल है।

अपीलकर्ता श्रीमती सुरिंदर कौर का विवाह 14 अप्रैल, 1973 को चंडीगढ़ में प्रतिवादी मदन गोपाल सिंह से हुआ था। 5 नवंबर, 1974 को, वह पहले वैवाहिक न्यायालय में अपने पति द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता के आधार पर उससे न्यायिक अलगाव का दावा कर रही थी। पति 16 जुलाई, 1974 को पहले वैवाहिक न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का दावा करने आया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 30 अगस्त, 1973 को पत्नी के उसके समाज से अलग हो जाने से वे बाधित हो गए थे। उपरोक्त दो मामलों के लंबित रहने के दौरान,पत्नी ने 9 जनवरी, 1975 को हिंदू विवाह अधिनियम (इसके बाद संक्षेप में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 27 के तहत संलग्न अनुबंध 'ए' और 'बी' में उल्लिखित संपत्ति के निपटान के

लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त दोनों मामलों के साथ इस आवेदन को भी लंबित रखा गया था. पति ने अधिनियम की धारा 13(1) (आईबी) के तहत याचिका दायर करने के लिए अदालत की अनुमति से अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका वापस ले ली। इस प्रकार 18 अप्रैल, 1977 को उन्होंने इस आधार पर तलाक की डिक्री के लिए याचिका दायर की कि पत्नी ने कम से कम दो साल की लगातार अवधि के लिए उन्हें छोड़ दिया था। तीन मामले, अर्थात् तलाक के लिए पति की याचिका; न्यायिक अलगाव के लिए पत्नी की याचिका और संपत्ति के निपटान के लिए पत्नी की याचिका का निपटारा 10 अक्टूबर, 1979 को प्रथम वैवाहिक न्यायालय के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया गया।पति की याचिका को स्वीकार कर लिया गया जबकि पत्नी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

(2) पति–पत्नी में से किसी ने भी अधिनियम की धारा 10 या धारा 13 के तहत याचिका में प्रथम वैवाहिक न्यायालय के फैसले और डिक्री को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना है। इस प्रकार, पति–पत्नी के बीच वैवाहिक बंधन का विघटन उन दोनों के लिए स्वागतयोग्य है। वे उस मोर्चे पर शांत हैं लेकिन संपत्ति के निपटान के मामले पर न्यायालय में हैं। चूंकि इस उद्देश्य के लिए पत्नी की याचिका खारिज कर दी गई थी, इसलिए उसने इस अपील के माध्यम से प्रथम वैवाहिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

> यह उल्लेखनीय है कि पहले वैवाहिक न्यायालय ने, उन पक्षों की दलीलों पर, जिनका संदर्भ बाद में दिया जाएगा, इस विषय पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

इस विषय पर निम्नलिखित मुद्दा –

"चाहे श्रीमती. सुरिंदर कौर हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 27 के तहत 9 जनवरी, 1975 को अपने आवेदन में दावा की गई संपत्ति की वापसी की हकदार हैं।"

(3) इस मुद्दे का निपटारा करते हुए न्यायालय का विचार था कि अधिनियम की खंड 27 के तहत आदेश केवल उस संपत्ति के संबंध में पारित किए जा सकते हैं जो पति और पत्नी दोनों की संयुक्त रूप से थी और याचिका में कोई दावा नहीं था कि संलग्नक 'ए' और 'बी' में उल्लिखित संपत्ति संयुक्त रूप से पक्षों की थी।उस परिसर में, इस मुद्दे पर पक्षों के साक्ष्य की जांच की गई, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनका मूल्यांकन और चर्चा नहीं की गई।यह इस मामले का दृष्टिकोण है जो पत्नी के लिए अस्वीकार्य है और वह अपील करती है।

अधिनियम की खंड 27 निम्नलिखित शब्दों में हैः—

"27. संपत्ति का निपटान।—इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही में, न्यायालय डिक्री में ऐसे प्रावधान कर सकता है जो वह विवाह के समय या उसके आसपास प्रस्तुत की गई किसी भी संपत्ति के संबंध में न्यायसंगत और उचित समझता है, जो पति और पत्नी दोनों की संयुक्त रूप से हो सकती है।"

(4) ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के ढांचे में इस धारा को शामिल करने का उद्देश्य अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही से निपटने के दौरान पक्षों के बीच कुछ संपत्तियों के संबंध में परिणामी आदेश पारित करना और प्रकृति का प्रावधान करना है। उन कार्यवाहियों में डिक्री पारित की जाएगी। जाहिर है, कार्यवाही समाप्त होने से पहले इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए और आदेश (डिक्री) के पारित होने के समय दिया जा सकता है। कानून में उक्त धारा जिस क्रम में दिखाई देती है, वह इसके लिए प्रावधान के बाद है अधिनियम की धारा 23 में डिक्री पारित करना और फिर धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और भरण–पोषण देने की शर्तों में उपचारात्मक प्रावधान करना, धारा 26 के तहत बच्चों की हिरासत का निर्णय लेना और पति और पत्नी दोनों की संपत्ति का संयुक्त रूप से निपटान करना। धारा 27 के तहत पत्नी, ताकि टूटे हुए या टूटे हुए विवाह से आहत पति या पत्नी के भाग्य को सुधारा जा सके। ऐसा भी प्रतीत होता है कि धारा 27 में शामिल संपत्ति के शीर्षक के बारे में कोई प्रश्न तय करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इसमें, या पति–पत्नी की सभी संपत्तियों तक विस्तार किया गया है। इसे ऐसी भाषा में रखा गया है ताकि इसका दायरा एक छोटे से दायरे में सीमित हो जाए। विश्लेषणात्मक रूप से, अनुभाग निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है: –

(I) यह न्यायालय के समक्ष अधिनियम के तहत लंबित एक वैवाहिक कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही के निर्णय से पहले संपत्ति के निपटान के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए।

(II) संपत्ति के निपटान के संबंध में डिक्री में प्रावधान करना न्यायालय का दायित्व नहीं है और यह उसके न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है;

(III) इस प्रकार बनाया गया प्रावधान, यदि कोई हो, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए जैसा कि न्यायालय पार्टियों के बीच इक्विटी के समायोजन और आसपास की सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानता है ;

(IV) आदेश में केवल वही संपत्ति शामिल होगी जो विवाह के समय या उसके आसपास प्रस्तुत की गई थी, जिसका अर्थ है कि न केवल विवाह के समय प्रस्तुत किया गया था, बल्कि विवाह से पहले या बाद में भी प्रस्तुत किया गया

था। वह विवाह के समय के निकट होना चाहिए न कि उस समय की विस्तारित सीमा के बाहर;

(V) इस प्रकार प्रस्तुत की गई संपत्ति या तो पत्नी या पति या दोनों को हो सकती है; और

(VI) जिस समय न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, उस समय संपत्ति संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की हो सकती है।

(5)अब यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि "संबंधित" शब्द आवश्यक रूप से स्वामित्व के अर्थ में संपत्ति के शीर्षक को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह केवल संपत्ति के साथ संबंध को दर्शाता है। भूमि एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से जोड़ने वाला शब्द है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त बताई गई समय सीमा के भीतर पति–पत्नी को प्रस्तुत की गई संपत्ति संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की हो सकती है, भले ही उन संपत्तियों में शीर्षक एक या दूसरे में निहित हो, या दोनों। एक सांसारिक उदाहरण देने के लिए, पति या किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत साड़ी! पत्नी को, साड़ी का मालिकाना हक पत्नी को हस्तांतरित हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह विशेष रूप से उसका होगा, न कि दोनों (पति और पत्नी) का संयुक्त रूप से, जैसा कि परिधान की प्रकृति से पता चलता है। इसी तरह, पति को उसी तरीके से प्रस्तुत किया गया सूट (विशेष रूप से पति से संबंधित होगा। किसी भी स्रोत से और उनमें से किसी एक से प्रस्तुत की गई संपत्तियां और वस्तुएं जो वर्तमान की प्रकृति के अनुसार हैं) या दाता के इरादे से, या पति–पत्नी की मौन सहमति से, पति और पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग में लाया गया है, तो यह कहा जा सकता है कि वे दोनों संयुक्त रूप से संबंधित हैं। ऐसी घटना का एक सांसारिक उदाहरण एक सेट का हो सकता है; वैवाहिक घर में संयुक्त उपयोग के लिए डाइनिंग टेबल और कुर्सियों की, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि आवंटित समय के भीतर किस पति/पत्नी ने इसे उपहार के रूप में प्राप्त किया। उक्त डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ स्पष्ट रूप से पति और पत्नी दोनों की संयुक्त संपत्ति होंगी और अधिनियम की धारा 27 के तहत आदेशों के अधीन होने में सक्षम होंगी।

(6) यदि कोई समानता स्वीकार्य है, तो इसे अधिनियम की धारा 25 में अंतर्निहित सिद्धांत के साथ खींचा जा सकता है। प्रत्येक पति/पत्नी की कमाई की क्षमता और अन्य संपत्ति, स्वामित्व के बावजूद, दोनों पति–पत्नी की आय को इस तरह से समान रूप से विभाजित करते समय ध्यान में रखा जाता है ताकि कम से कम एक को दूसरे की कीमत पर पर्याप्त रूप से बनाए रखा जा सके। विवाहोत्तर सामाजिक स्थिति उसी तरह, अधिनियम की धारा 27 उस संपत्ति के बंटवारे का प्रावधान करती है जो पति–पत्नी को विवाह के समय या उसके आसपास व्यक्तिगत या सामूहिक रूप

से उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी, और जो उनके जीवन के एक तरीके के रूप में सामने आई थी। उनके दैनिक जीवन में संयुक्त उपयोग और इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए 'संबंधित' है। यदि विवाह बाधित होता है, तो ऐसे संयुक्त रूप से संबंधित लेखों को उपचारात्मक राहत के उपाय के रूप में पति–पत्नी के बीच बांटने के लिए न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होगी।

(7) कामता प्रसाद बनाम श्रीमती में। ओम वती, (1), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अधिनियम की धारा 27 के दायरे की जांच करते हुए उसमें विशेष रूप से पति या पत्नी की संपत्ति से संबंधित डिक्री पारित करने की अदालत की शक्ति का वर्णन किया; अधिनियम के तहत कार्यवाही में निहित शक्ति के रूप में। यह भी माना गया कि अनुभाग में शब्द "जो पति और पत्नी दोनों के संयुक्त रूप से संबंधित हो सकते हैं" संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों से निपटने के लिए एक सक्षम शक्ति को प्रतिबिंबित करते थे, लेकिन अकेले ऐसी संपत्तियों पर न्यायालय की शक्ति को सीमित नहीं करते थे। इस दृष्टिकोण में, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि धारा 27 के दायरे से बाहर आने वाली संपत्ति के प्रयोजनों के लिए वैवाहिक न्यायालय को एक सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करना चाहिए। अब, हालांकि, विधायिका ने सलाह दी है, और विवाह संस्था की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए, मुकदमे के साथ–साथ अपीलीय चरणों में वैवाहिक मामलों के सबसे शीघ्र निपटान का आश्वासन दिया है, जिससे उन्हें समयबद्ध किया जा सके। यदि सभी प्रकार के निपटारे के प्रश्न हैं धारा 27 में परिकल्पित संपत्तियों के अतिरिक्त संपत्ति के मामले में एक सिविल न्यायालय के रूप में वैवाहिक न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना था, क्योंकि यदि एक नियमित मुकदमे की सुनवाई की जाती है, तो वैवाहिक विवादों को अत्यधिक गति से आगे बढ़ाना लगभग असंभव होगा। यही कारण है कि, चूंकि संपत्ति से संबंधित आदेश को डिक्री का हिस्सा बनाना होता है, इसलिए ऐसी संपत्ति से निपटने का विवेक न्यायालय पर छोड़ दिया गया है, यदि ऐसा हो सकता है, तो अत्यधिक तेजी के साथ, और अन्यथा पार्टियों को एक नियमित मुकदमे में मामले को उत्तेजित करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। हालाँकि, कामता प्रसाद की सहजता (सुप्रा) में इलाहाबाद का निर्णय विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1976 से पहले का है। अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत यह मिसाल मौजूदा प्रश्न की पकड़ में नहीं आती है। उक्त निर्णय में, "संयुक्त रूप से स्वामित्व" को "संयुक्त रूप से स्वामित्व" के बराबर किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान के साथ, "संयुक्त रूप से जुड़ें" अभिव्यक्ति की व्याख्या धारा 27 के प्रयोजनों के लिए बहुत संकीर्ण है, इसके दायरे में कटौती के लिए किसी भी तर्क से रहित है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। (8) एम. डी. कृष्णन बनाम एम. सी. पद्मा (2) में मैसूर उच्च न्यायालय ने यह *निर्णय लिया कि खंड 27 के तहत* दावा की जाने वाली संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो विवाह के समय या उसके आसपास उपहार के रूप में प्राप्त हुई होगी और इसका अर्थ विवाह के समय के करीब

या उसके आसपास होना चाहिए, चाहे वह उससे पहले हो या बाद में।उस मामले में निर्णय ने एक पत्नी और एक पति के बीच विवाद को सुलझाया, जहां पति ने रुपये के मूल्य के चांदी के बर्तन और सामान वापस करने का दावा किया था। उसे 1,000 रुपये का अनुदान दिया गया। उनके मूल्य के रूप में 600 और रुपये के प्रतिधारण की अनुमति। विवाह के समय दूल्हे को उपहार के रूप में पारंपरिक 'वर दक्षिणा' के रूप में अकेले पति को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। बेंच ने पति और पत्नी को संयुक्त रूप से शादी के समय या उसके आसपास चांदी की वस्तुओं का उपहार दिया। यह इस दृष्टिकोण से है । बताया गया कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा 27 के तहत विचार किए गए उपहार न केवल संयुक्त रूप से पति–पत्नी के हैं, बल्कि उन्हें विवाह के समय या उसके आसपास संयुक्त रूप से दिया जाना चाहिए। यह फिर से, बेंच का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ, किसी भी तर्क से रहित निर्णय है। धारा 27 यह इंगित नहीं करती है कि इसके तहत कवर किए जाने वाले उपहार वे हैं जो विवाह के समय या उसके आसपास संयुक्त रूप से प्राप्त किए गए हैं, बल्कि इसमें केवल वे संपत्तियां शामिल हैं जो संयुक्त रूप से पति–पत्नी की हैं।

(9) न्यायालय में उद्धृत तीसरा निर्णय, भाई शेर जंग सिंह आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) और दूसरा बनाम श्रीमती विरिंदर कौर (3), मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का निर्णय था। , जिसमें इस प्रकार देखा गया है:

“हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 एक वैवाहिक विवाद का निर्णय करते समय एक न्यायालय को संपत्ति के संबंध में एक डिक्री पारित करने का अधिकार देती है जो संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की हो सकती है।यह खंड एक पीड़ित पत्नी को एक नागरिक उपचार प्रदान करती है और किसी भी तरह से आपराधिक शिकायत दर्ज करने के उसके अधिकार को नहीं छीनती है यदि उसके पति द्वारा उसकी संपत्ति का आपराधिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है।

(10) उन्होंने कहा कि बेंच का फैसला मौजूदा सवाल के लिए कोई मिसाल नहीं है।

(11) अधिनियम की धारा 27 के तहत याचिका में, पत्नी ने शादी के समय या उसके आसपास उसे दी गई संपत्ति/वस्तुओं की वापसी का दावा किया है, जिसका कब्ज़ा पति और उसके रिश्तेदारों के पास है। सामान की सूची अनुलग्नक 'ए' और 'बी' में विस्तृत थी। इसमें आगे दावा किया गया है कि यदि अनुलग्नकों में वर्णित उक्त संपत्ति/वस्तुओं को पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्षतिग्रस्त, उपयोग या अनुपयोगी बना दिया गया है, तो उसकी लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह दावा किया गया था कि अधिनियम की धारा 10 के तहत पारित होने वाले डिक्री में एक उपयुक्त प्रावधान विवाह के समय या उसके आसपास उसे दी गई

संपत्ति/वस्तुओं की वापसी के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि अनुलग्नकों में बताया गया है। कथित तौर पर विवाह के समय या उसके आसपास याचिकाकर्ता को प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक 'ए' में उल्लिखित वस्तुएं मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आती हैं – (1) आभूषण और कपड़े जो अपने स्वभाव से केवल उसके दैनिक उपयोग के लिए होते हैं और (2) दलों के सामान्य उपयोग के लिए वस्तुओं । अनुलग्नक 'बी' में मोटे तौर पर पति को प्रस्तुत संपत्ति/वस्तुओं की सूची शामिल है जो अपने स्वभाव से केवल उसके उपयोग के लिए थीं और अन्य उसके रिश्तेदारों के उपयोग के लिए थीं। पति ने अपने लिखित बयान में सामान अपने पास होने से इनकार किया है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि पत्नी ने पहले ही अनुबंध 'ए' और सीरियल नंबर 2 में क्रम संख्या 1, 2, 5 से 8 तक उल्लिखित वस्तुओं को ले गई है; अनुलग्नक 'बी' में। उन्होंने अनुबंध 'ए' में क्रम संख्या 3 और 4 पर और अनुबंध 'बी' में क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित सामान को क्रम संख्या 3 से 12 तक के सामान अनुलग्नक 'बी' में उनके रिश्तेदारों को विवाह के समय या उसके बाद में दिए जाने से भी इनकार किया है। .. .उन्होंने यह भी दावा किया है कि उपरोक्त वस्तुओं को अधिक मूल्यांकन दिया गया है और वे धारा 27 के दायरे में नहीं आते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, पहली वैवाहिक अदालत ने सबूतों को मार्शल नहीं किया, हालांकि सुझाव देते हैं–करम सिंह (आर. डब्ल्यू. 2), ब्रह्मजीत कालिया (आर. डब्ल्यू. 3) और पत्नी के पिता शांगरा सिंह (आर. डब्ल्यू. 4), और सुरिंदर कौर (आर. डब्ल्यू. 6), पत्नी ने संपत्तियों/वस्तुओं के संबंध में गवाही दी है। स्वयं पी. डब्ल्यू. 5 के रूप में पति ने पत्नी के दावे का विरोध किया है।

(12) निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही को अंतिम रूप देने में पांच साल से अधिक का समय लग गया। किसी वैवाहिक मामले में इतनी लंबी सुनवाई अनावश्यक है और संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम की भावना के विपरीत है। वैवाहिक क्षेत्राधिकार एक विशेष प्रकृति का है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी कार्यवाहियों को सामान्य नागरिक कार्यवाही की स्थिति में डालने से न केवल कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा, बल्कि दुखद परिणाम भी होंगे। भारत में जहां हिंदू विवाह आमतौर पर पति–पत्नी के अलावा अन्य लोगों द्वारा तय किया जाता है, इसके टूटने से समाज के सदस्यों में हलचल मच जाती है। यह एक कारण है कि वैवाहिक न्यायालयों द्वारा दिए गए अधिकांश निर्णय, जो पूरी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत आते हैं, बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रभावित करने वाले निर्णय हैं। यदि संपत्ति के निपटान का विवादित मुद्दा वैवाहिक न्यायालय का ध्यान अन्य कार्यवाहियों पर केंद्रित करता है जिसके संबंध में डिक्री मांगी गई है, तो निर्णय तत्परता से नहीं दिया जा सकता है। धारा 27 के तहत परिकल्पित संपत्ति का निपटान केवल डिक्री का हिस्सा बन सकता है, अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, यदि यह अधिक समय लेने के बिना निपटान करने में सक्षम है ताकि डिक्री पारित होने में देरी न हो। लेकिन अगर न्यायालय खुद को दलीलों की प्रकृति, विचारों के विचलन और सबूतों की अनुमानित मात्रा से नियमित प्रतिस्पर्धा का सामना करता हुआ पाता

है, तो डिक्री के एक हिस्से के रूप में संपत्ति के निपटान के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार करना उसके अधिकार में होगा। संपत्ति मामले का निपटान न्यायालय के समक्ष मुख्य कार्यवाही से अधिक नहीं हो सकता जिसके संबंध में डिक्री पारित करना आवश्यक है।

13) मौजूदा मामले में, साक्ष्यों का बड़ा हिस्सा संपत्ति के सवाल के निपटारे पर हावी है। चूँकि न्यायालय ने आवश्यक मुद्दा तैयार किया और न्यायालय के बहुमूल्य समय का उपयोग करते हुए उस पर साक्ष्य दर्ज किए, इसलिए बहुत देर हो चुकी थी कि धारा 27 के तहत पत्नी के आवेदन को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके द्वारा दावा की गई संपत्तियाँ अनुलग्नक 'ए' और 'बी' को संयुक्त रूप से पति–पत्नी का नहीं माना गया है। सबसे पहले, न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या पति–पत्नी में से किसी एक को किसी भी स्रोत से प्राप्त उपहार वास्तव में प्राप्त हुए थे और अनुभाग में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हुए थे। फिर दूसरे स्थान पर न्यायालय को यह देखना होगा कि उपहार या भेंट में से कौन–सा उपहार पति–पत्नी के पास संयुक्त रूप से है। इस दृष्टि से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी की दलील संयुक्त स्वामित्व की दलील से पूरी तरह वंचित है।

(14) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, गुण–दोष के आधार पर मामले की जांच करना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि इसे वैवाहिक या नागरिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में नए सिरे से विचार करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। आवश्यक रूप से, निचली अदालत को मुद्दे संख्या 2 पर एक निष्कर्ष दर्ज करने और अंतिम निपटान के लिए मामले को इस अदालत में वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। निष्कर्ष को मौजूदा सामग्री के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। मामले के रिकॉर्ड को प्रथम वैवाहिक न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 21 मार्च, 1980 को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जाए और फिर अपील को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। आंशिक रूप से सुना हुआ।

एम. एम. पुंछी, जे.–

(मौखिक)।

(15)इसे 10 मार्च 1980 के मेरे आदेश की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए। वैवाहिक न्यायालय ने एक निष्कर्ष दिया है कि अनुलग्नक 'ए' के क्रम संख्या 3, 4, 7 और 8 में उल्लिखित वस्तुएं पत्नी–अपीलकर्ता को दहेज में दी गई थीं और बारात प्रस्थान के समय प्रतिवादी पति द्वारा अपने घर ले जाया गया था और उक्त वस्तुएं अभी भी प्रतिवादी पति के पास हैं। इस निष्कर्ष ने उक्त! 'अदालत के आदेश को

आकर्षित किया है कि पत्नी–अपीलकर्ता इन सभी वस्तुओं की वसूली का हकदार है। इस निष्कर्ष पर पति–प्रतिवादी द्वारा आदेश 41 नियम 26, सिविल प्रक्रिया संहिता सी.एम. क्रमांक 1663–सी.।। सन् 1980 के तहत क्रॉस–आपत्ति के रूप में आपत्ति जताई गई है ,प्रथम अपील का निर्णय किया जा रहा है। अपीलकर्ता को उसके वकील के माध्यम से 8 मई, 1980 को नोटिस दिया गया था और इस प्रकार उक्त विविध आवेदन मुख्य मामले के साथ निपटान के योग्य होगा।

(16) शुरुआत में, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पहले वैवाहिक न्यायालय ने पति के कब्जे में पाई गई वस्तुओं को विभाजित नहीं किया, जो प्रत्येक पति या पत्नी के लिए समान रूप से निर्धारित करने में सक्षम थे। आवश्यक रूप से, निष्कर्ष का परीक्षण मुख्य रूप से यह स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में अनुबंध 'ए' के क्रम संख्या 3, 4, 7 और 8 पर लेख पति के पास हैं और यदि हां, तो उनमें से जो वह अपने उपयोग के लिए रख सकता है और अन्य को अपनी तलाकशुदा पत्नी के पक्ष में समर्पित कर दिया जाए। दोनों पक्षों के विद्वान वकील इस समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से और तलाकशुदा पति–पत्नी को कम से कम कष्ट पहुंचाए बिना सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। पत्नी–अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री उज् अगर सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जहां तक क्रम संख्या 7 और 8 में उल्लिखित लेखों का सवाल है, वह याचिका पर दबाव नहीं डालेंगे और उनके अनुसार, वर्तमान याचिका के प्रयोजनों के लिए उन लेखों को दायरे से बाहर कर दिया गया माना जाएगा। एकमात्र विवाद क्रमांक 3 और 4 पर उल्लिखित लेखों को लेकर है और जिन पर पार्टियों के मूल्य–वार और उपयोग–वार तुलनात्मक दावों का निपटारा किया जाना है। वहाँ फिर से पार्टियों ने अपने वकील के माध्यम से सुझाव दिया कि क्रम संख्या 3 में उल्लिखित लेखों में से, पति–प्रतिवादी फोल्डिंग हार्ड बेड का सेट अपने पास रखेगा और शेष सामान अर्थात् सोफासेट, ड्रेसिंग टेबल, सनमाइका सेंट्रल टेबल और ड्रेसिंग स्टूल वापस कर दिया जाएगा। उनके द्वारा पत्नी को उसके उपयोग के लिए उसी स्थिति में दिया जाता है जिस स्थिति में वे आज मौजूद हैं। इसी तरह, उसी भावना के रखरखाव में, पति डिनर सेट स्टील (एक) और आइटम नंबर 4 से चाय का सेट अपने पास रखेगा और शेष अर्थात् प्रेशर कुकर हॉकिन्स, ढक्कन के साथ दो तांबे के पतीले, एक तांबे की प्रैट और एक प्रेस पत्नी–अपीलकर्ता को उसी स्थिति में लौटाया जाएगा जिस स्थिति में वे आज मौजूद हैं। पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए सुझाव निष्पक्ष और उचित प्रतीत होते हैं और अपीलीय चरण में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के तहत इस याचिका को निपटाने के निर्णय के आधार के रूप में अपनाए जाने योग्य हैं। इससे प्रश्नगत अनुच्छेदों पर संबंधित पक्षों के दावे को प्रस्तुत करने के लिए प्रश्न पर साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की इस न्यायालय की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

(17) जैसा कि एक परिणाम है; जो पहले कहा गया था। इसलिए, यह आंशिक रूप से

अनुमत है और पति–प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त लेखों को, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है, अपने उपयोगकर्ता के लिए पत्नी–अपीलार्थी को उस स्थिति में तुरंत सौंप दे जो आज मौजूद है और अपनी ओर से किसी भी कार्य या चूक द्वारा इसके विनाश, प्रतिस्थापन या न्यूनतमकरण में लिप्त न हो।इस निर्देश को तलाक के मुख्य फरमान के परिशिष्ट के रूप में लिया जाना चाहिए। अपील की इस याचिका में कोई लागत नहीं होगी।

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

हरमिंदर कुमार